THE BUDGET (GENERAL), 1986-87—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further discussion on the General Budget. Dr. Govind Das Rich-hariya.

डा. गोविन्द दास रिछारिया (मध्य-प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया और आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा बजट उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर से यह भी कह देना उचित समझता हूं कि जिस समय से स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने हमारे संविधान में यह धारा शामिल करा दी है कि हमारे राष्ट्र को लोकतंत्र के आधार पर समाजवाद तक पहुंचाना है, देश में समाजवाद लाना है। उस दिन से यह निश्चित हो गया है कि हमारी राजनीतिक पार्टी और उसके साथ-साथ सारे राजनीतिक दल गरीबी मिटाने के लिए युद्ध के मोर्चे पर खड़े हैं। योजनाओं के द्वारा हमारी केन्द्रीय सरकार को, प्रांतीय सरकारों को, हमारे देश के कार्यकर्ताओं को मिल कर युद्ध स्तर पर गरीबी मिटाने के लिए कार्य करना है। अतः सबसे पहला लक्ष्य यह है कि हम विकास की योजनाओं को, गरीबी मिटाने की योजनाओं को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करें, उनको इस तरह से शुरू करें, इस तरह से चलाएं कि लोगों को दिखाई दे कि जिस तरह स्वतंत्रता के आन्दोलन में एक निश्चित लक्ष्य था, सारा देश जानता था कि हमको यह लक्ष्य प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सारे देश में एक आन्दोलन हो रहा था। आपने महसूस किया होगा, सारा देश महसूस करता है कि लोकतंत्र के आधार पर जो हमको समाजवाद लाना है उसके लिए युद्ध स्तर पर देश आन्दोलित नहीं हुआ। तो मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी और योजनाकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पुनर्विचार करें, इस पर सोचें कि हम किस तरीके से अपनी योजनाओं में यह परिवर्तन करें कि सारे राष्ट्र के गरीबों को, सारे देश के निवासियों को दिखाई दे कि हमको एक आन्दोलन के तरीके से, युद्ध के स्तर पर विकास के कार्य में, राष्ट्र निर्माण के कार्य में, गरीबी मिटाने के काम में एक होकर चलना है।

अब मैं बहुत संक्षेप में थोड़े से सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे वित्त मंत्री जी को, हमारे योजनाकारों को एक तारीख निश्चित कर देनी चाहिए कि इस तारीख तक हम सारे राष्ट्र में इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि हमारे देश में चाहे कोई जंगलों में रहता हो या शहरों में वह गरीबी की रेखा के नीचे नहीं होगा। हम काम का बंटवारा करें कि प्रान्तीय सरकारों को क्या करना है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या करना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या करना है। तब आपका यह विकास का कार्य, गरीबी मिटाने का काम युद्ध स्तर पर चलेगा।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि अगर आप देश के रहने वालों को भागीदार बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको सारे राष्ट्र में, सारे देशों में पंचायती राज का विस्तार करना होगा। पहले गांव सभा, क्षेत्रीय समिति, दूसरे ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करनी होगी जिससे विकास का काम सारे राष्ट्र में हो सके। मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप योजनाओं का क्रियान्वयन इन हाथों को सौंप दें, उनको दे दें, गांव की जितनी विकास योजनाएं हैं उनका जिम्मेवार ही ग्राम का प्रधान, ग्राम समिति और गांव सभा के लोग वहां के निवासी। उस के बाद जो आप की क्षेत्रीय-समितियों के काम हैं वह भी क्षेत्रीय समिति को सुपुर्द करें। उन का कार्यान्वयन क्षेत्रीय समिति और ब्लाक समिति के अंतर्गत हो। इसी प्रकार जिले के अंतर्गत जितनी योजनायें चलती हैं उन का उत्तरदायित्व आप जिला समिति को सौंपिये। निःसंकोच सौंपिये। तभी आप देखेंगे कि आप की योजनाओं का काम जो ढीला दिखाई देता वह बहुत तेजी से चलेगा और आप अपने लक्ष्य तक बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और आप को आप का काम युद्ध स्तर पर चलता हुआ दिखाई देगा। आप के जितने विशेषज्ञ हैं उन कामों में जो टेक्निकल मदद है वे देते रहें, आप के विशेषज्ञ उन को देखते रहें, उनकी निगरानी करते रहें लेकिन योजनाओं

[डा. गोविन्द दास रिछारिया]

का कार्यान्वयन निश्चित तौर पर पंचायती राज विभाग को या ग्रामों से ले कर जिला स्तर तक दे दिया जाय। इसी तरह शहरी, नगरी विकास का काम, जो बहुत बड़े शहर हैं वहां महानगरपालिकाओं को और जो छोटे शहर हैं उन को नगरपालिकाओं को और उससे छोटे नगरों का काम नागरिक संगठनों को सौंप दिया जाय चाहे वे टाउन एरिया हों या नोटिफाइड एरिया हों। इस तरह से जब आप वहां के निवासियों को अधिकार सौंप देंगे, उन के विकास का कार्य सौंप देंगे तब आप का गरीबी मिटाने का युद्ध तेजी से चलेगा।

मैं निश्चित तौर पर अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ मौलिक परिवर्तन किये हैं। जलसंसाधन मंत्रालय बना कर जल के इस्तेमाल में एक नयी जलनीति आ रही है। इस से देश में बड़ा परिवर्तन होगा और राष्ट्र में अभी तक जल का जो पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था, अभी तक बाढ़ से जो विध्वंस होता था और सामूहिक तौर पर तो नदियों का विवाद चल रहा था, नर्मदा बहुती रहती थी उस का विवाद था, बेतवा बहती थी उस का विवाद था, सोन बहती थी उस का विवाद था और उन के पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन यह जलसंसाधन मंत्रालय बन जाने से अब सामूहिक तौर से सारे देश के जल का किस तरह इस्तेमाल हो, सारे देश के स्तर पर कैसे बाढ़ को नियंत्रित किया जाय, कैसे सारे देश के लाभ के लिये बिजली निकाली जाय इस पर विचार हो सकता है और इस से निश्चित तौर पर लाभ होगा।

इसी तरह से केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया है उस से भी निश्चित तौर पर लाभ होगा और इस में परिवर्तन होने से काफी लाभ सामने आयेंगे। इसी तरीके से यह भी निवेदन है कि भूमि सुधार के लिये भी सामूहिक तौर से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आप की आबादी बढ़ी लेकिन जमीन का रकबा, उस का क्षेत्र-फल जितना आप के पास है वह बढ़ना नहीं है। इस लिये आवश्यक है कि राष्ट्र के अंतर्गत खेती के बाहर जितनी जमीन है उस में कुछ सुधार करें। आप के राष्ट्र में जितना रकबा बंजर पड़ा हुआ है उस में सुधार करके उसको खेती के नीचे लाने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारी योजनाओं में यह भी आवश्यक है कि जितना रकबा खेती के अंदर है वहां हर खेत को पानी मिले चाहे वह लघु सिंचाई से हो या मध्यम सिंचाई योजनाओं से हो या बड़ी सिंचाई योजनाओं से हो। चाहे कितना ही छोटा किसान हो जब तक उस के पास पानी नहीं पहुंचेगा तब तक गांवों का विकास मुश्किल मालूम होता है और इसी प्रकार जो आप के लघु और छोटे उद्योग हैं, जितना कच्चा माल गांवों में पैदा होता है वह चाहे खादी ग्रामोद्योग कमीशन से हो या लघु उद्योग कमीशन से उसकी गांवों के स्तर पर ही खपत होने की आवश्यकता है। आप को एलान करना पड़ेगा कि हर गांव सभा अपने गांव के स्तर पर उद्योग कायम करे और जो गरीब नौजवान जिस के पास जमीन नहीं है, जो खाली है अगर वह उद्योग मांगता है तो गांव सभा का उत्तरदायित्व हो कि वह फौरन उस को कोई उद्योग दे, कोई काम दे। यह क्षेत्रीय समितियों का उत्तरदायित्व है कि अगर उनके क्षेत्र के अन्दर कोई काम मांगता है तो उसके पास इतना काम हो कि वह नौजवान उसको काम दे सके। तो इस तरह से जब आप हर व्यक्ति को काम देंगे, हर गरीब को काम देंगे, हर खेत पर पानी भिजवा देंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य आप निश्चित करेंगे, वह पूरे हो सकेंगे। गरीबी मिटाने का जो लक्ष्य निश्चित करेंगे, हर परिवार से गरीबी दूर करने की जो तारीख निश्चित करेंगे, उसको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का जो समय निर्धारित करेंगे, वह पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सकेंगे।

अतः मैं आपके बजट का समर्थन करते हुए जो मैंने आपसे सुझाव के रूप में निवे-दन किया है, उस पर विचार करेंगे और उसे लागू करेंगे। इतना ही मैं आपसे अनु-रोध करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिसिंह नलवा (हरियाणा) : उप-सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बजट जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह बहुत ही अच्छा बजट है।

असलियत में कोई भी बजट अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा तो उसके इम्पलीमेंटेशन के आधार पर कहा जा सकता है। जो बजट में राशि रखी गई है अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों के लिए उसके देश के अन्दर रहने वाले गरीबों, बेरोज-गारों, जवानों और किसानों की भलाई के लिए रखी गई है। उसका अगर प्रापर इंप्ली-मेंटेशन हो जाए और जिन लोगों की भलाई के कामों के लिए यह राशि रखी गई है उससे उनको पूरा लाभ मिल सके तो वित्त मंत्री जी ने जिस भावना से यह बजट पेश किया है, वह पूरी हो सकती है। वह भावना अगर पूरी हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि देश के अन्दर चार चांद लग सकते हैं और देश और प्रगति कर सकता है।

महोदय, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके लिए यह जरूरी चीज है कि उसका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से हो। इंप्लीमेंटेशन तभी सही ढंग से हो सकेगा जब कि उसके लिए ईमानदार आदमी, सही आदमी, आउटस्पोकन आदमी संबद्ध विभागों में नियुक्त किये जाएं। ईमानदार, आनेस्ट लोग जब तक इन इंप्लीमेंटेशन के लिए इंचार्ज नहीं बनाएंगे तब तक आपका प्रपो-जल्स और आपकी स्कीमें कार्यान्वित नहीं हो सकेगी और जिन लोगों को उनसे लाभ होना चाहिए वह उसका अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। पूरा लाभ बजट का लोगों को तभी मिल सकेगा जब कि उस का सही ढंग से कार्यन्वयन हो। ऐसा न होने पर देश में अशान्ति और अस्थिरता का वातावरण पैदा होता है।

श्रीमन्, देश के अन्दर शान्ति रखने का दायित्व तीन प्रकार के लोगों पर होता है और वह तीन वर्ग हैं किसान, मजदूर और सिपाही। सिपाही चाहे फौज का हो या खेत का हो, वह देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का आधार है। इसके बारे में जो राशि वित्त मंत्री जी ने रखी है, मैं समझता हूं कि पूरी इमानदारी के साथ उसका कार्यान्वयन हो और वह लोगों तक पहुंचाई जा सके, उसका लाभ लोगों को मिल सके तो उससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और लोग एजिटेशन या अराजकता नहीं फैलाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश के अन्दर रेवोलूशन, क्रांति इन्हीं तीन वर्गों द्वारा आई है। किसान जब खेत से हट जाता है, बेरोजगार हो जाता है, उसकी खेती करने में दिक्कतें होती हैं तो वह एजिटेशन करता है। मजदूर को जब काम नहीं मिलता, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता तो वह एजिटेशन की बात सोचता है। सिपाही जो देश की सुरक्षा करता है अन्दर से, बाहर से, देश उसके हकूक का उसके हितों का जब एक्सप्लायटेशन होता है तो वह एजिटेशन की बात सोचता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा वित्त मंत्री जी से कि यह जो बजट लाए हैं, वह ठाकुर हैं और खुबसूरत चेहरे वाले इंसान हैं, आधी तकलीफ तो वित्त मंत्री जी के दर्शन करने से दूर हो जाती है, अगर उसी भावना से वह प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करा दें तो कहता हूं कि इससे अच्छा बजट देश की बहबूदी के लिए और कोई हो नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए, किसानों के अन्दर अमन रखने के लिए, मजदूरों को राहत देने के लिए, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए, सिपाही को आराम देने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए हमें कदम उठाने चाहियें। तीन क्लासेज हैं देश में जिनको सिर्फ अमन चाहियें। वे कौन सी हैं? डाक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और तीसरे टीचर्स हैं। इनको भी पूरी तरह से अमन चाहिए। अमन सिर्फ इतना ही है कि मिसाल के तौर पर, बिजली बोर्ड है इसके अन्दर जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं बड़े क्वालिफाइड होते हैं। उनको मालूम होता है कि प्लांट के जेनरेशन में कहां गड़बड़ी है, किस तरह से इसमें एफिशियंसी लाई जा सकती है। इनके ऊपर बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया जाता है

[श्री हरि सिंह नलवा]

वह आई. ए. एस. आफिसर होता है या ब्यूरोक्रेट्स होता है । इन लोगों को उनके सिरपर बैठा दिया जाता है । जो इंजिनियर्स होते हैं जो टैक्नीशियंस होते हैं उनके हार्ट के अन्दर बर्निंग्स होती है । वे यह समझते हैं कि एक अनपढ़ को हमारे ऊपर लाकर बैठा दिया । यह बात नहीं कि आई. ए. एस. आफिसर पढ़ा लिखा नहीं होता, वह बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन उसको टेक्नीकल नालिज नहीं होती, उसका ए बी सी भी उसको नहीं पता होता इसलिए वे इसको अनपढ़ बताते हैं । उनके हार्ट में बर्निंग होती है । ऐसे महकमों के अन्दर जिसके ऊपर किसान, मजदूर और सिपाही सब का दारोमदार होता है, वहां पर टेक्नीशियंस, इंजिनियर्स काम करते हैं उनका हैड, चेयरमैन किसी आई. ए. एस. आफिसर को बना दिया जाता है । हम यह चाहते हैं कि इनका हैड किसी टैक्नीशियन्स को, इंजीनियर्स को ही बनाना चाहिये ताकि उसके नीचे काम करने वाला कोई भी आदमी सबोर्डीनेट अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो वह उसको पकड़ सकता है । वह जाकर यह पता लगा सकता है कि कहां पर गड़बड़ हुई है । अगर कोई प्लांट फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है तो वह जाकर पता लगा सकता है कि यह फुल कैपेसिटी में किस कारण काम नहीं कर रहा है वहां जाकर उसमें सुधार करा सकता है । इस के ऊपर सारे देश की इकोनामी निर्भर करती है । इसी तरह टीचर्स भी हैं । इनकी तालीम से नेशन का करेक्टर बनता है, नेशन बनता है । देश को खूबसूरत बनाते हैं । टीचर्स की ट्रांस्फर कर दी जाती है । ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये अपनी मर्जी से इनकी ट्रांसफर दूर-दराज के इलाकों में कर देते हैं अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना कर । उनकी ट्रांसफर इनकी अनचाही जगहों पर कर दिया जाता है । उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है । इससे क्या होता है कि वह काम करना छोड़ देते हैं । जिस भावना से, जिस देशभक्ति की भावना से वह काम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते । इसमें सरकार का लगता कुछ नहीं है । सरकार को देश को ऊंचा उठाने के लिये जो भी हुक्मरान हैं, जो हैड आफ द डिपार्टमेंट हैं, चाहे मिनिस्टर हों उनका प्रेस्टीज नहीं होना चाहिए । उनको जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । इसमें कोई इज्जत और बेइज्जती का सवाल नहीं है । जो अच्छा काम हो उसको मान लेना चाहिए और यह प्रेस्टीज का सवाल छोड़ देना चाहिए ।

आज के जमाने में जब कि हमारे देश के अन्दर एक नौजवान इतना साफ सुथरे ख्याल वाला प्रधान मंत्री हमारे पास हो प्रोग्रेसिव ख्याल वाला प्रधान मंत्री हमारे पास हो उस वक्त अगर देश तरक्की नहीं करेगा तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान किस वक्त तरक्की कर सकेगा । हम को चाहिए कि जहां भी कहीं डिसआनेस्ट, इनएफिशियंट लोग बैठे हुए हैं, साइकोफेंट लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर सरकार को सख्ती करनी चाहिए । उनको बता देना चाहिए कि अगर वे बाज नहीं आयेंगे तो पब्लिकली उनको एक्सपोज किया जायेगा । हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि ऐसे आदमियों को पब्लिकली एक्सपोज करके प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत किये जायें ताकि वह तेजी के साथ देश को 21वीं सदी में ले जा सके । यह काम करने के लिए चाहे जिस पार्टी के लोग हों, यहां के एम पीज, एम एल एज जो बैठे हैं चाहे वे इस पार्टी के हों चाहे अपोजिशन के हों, उनको देश के लिए अस्सेट साबित होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं । लाइबिलिटी वे हो लोग साबित होते हैं जो इनएफिशियंट हैं, जो डिसआनेस्ट हैं । ऐसे लोगों से हम को सावधान रहना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं यह पुरजोर प्रार्थना करूंगा, वित्त मंत्री जी का एश्योरेंस भी चाहूंगा कि इस बजट के प्रपोजल्स के इम्पलीमेंटेशन में हैड आफ द डिपार्टमेंट जो भी आप बनायें वे इसका प्रोपर्ली इम्पलीमेंटेशन करें । वह ईमानदार और आनेस्ट हो । डिसआनेस्ट लोगों को वहां से हटाया जाए ताकि देश के किसानों को, गरीबों को, सिपाहियों को, टीचर्स को, इंजीनियर्स को राहत मिले और देश अमन से चल सके । किसी भी देश का जब तक उसका सिपाही, किसान और मजदूर अमन से काम कर रहा है उस देश की इंटेग्रिटी और यूनिटी को कभी

खतरा पैदा नहीं हो सकता । देश को जब खतरा होगा तो इन्हीं तीन वर्गों से होगा, देश को डेंजर होगा तो इन्हीं क्लासेज से होगा क्योंकि ये लोग हाथ से काम करने वाले होते हैं और हाथ से काम करके खाते हैं । ये लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बसर करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में डिप्टी चेयरमैन साहब को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to complement the Finance Minister, because he has started the process of budget-making this year in a novel way. First, he has consulted all the interested parties before he framed the budget proposals;. Now, he has plans to consult the economists, agriculturists and other interested parties after the budget. This is a very good precedent follower by the hon. Finance Minister and I must compliment him for that.

Sir, in my speech on the price hike, T had stated that we have passed an innocuous Bill, called the Central Excise (Tariff Amendment"* Bill, 1985, in the last session of Parliament in which it was stated that there will be rationalisation of traiff structures. I apprehended at that time that under the garb of that amendment new levies will be imposed and the Government will be able to amass further amounts on accounts of those levies. I pointed it out to the hon. Finance Minister several days before the Budget that while the Central Excise (Tariff Amendment) Bill, 1985 was bems enacted in the last session, he had stated that there will be n_0 difference or there will be no escalation or there will be no new levy as a result of this amendment.

I pointed out that because that new tariff was to b_e applicable on 28th of February, innocuously and inadvertently shawls were coming under the purview of a 12 per cent excise tax. I must compliment him that he took note of it, he registered it in his mind and immediately looked into the matter. A notification was issued exempting shawls as early as on 27th. Here, I do not agree with Mr. Lai K. Advani when he said that certain notifications were being issued on the eve of the budget. As I have mentioned, the aims and objects of the Bill were very clear and no fresh taxes were levied. It was pointed out to the hon. Finance Minister and he rectified it. If such notifications are issued on the eve of the Budget, what is the harm in it? I don't think there is anything bad about it. Some rectification like (his has to be done.

I would now come to the Budget. Mr. Ptanab Mukherjee stated the day before yesterday in Parliament that the long-term fiscal policy was commiting the Government t_0 some tax structure which would bind them for several years to come In this connection, he quoted Article It? of *ft** Constitution. Sir, I have gone through this article and it says:

"112. (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of $Indl_a$ for that year, in this Part referred to as the 'annual financial statement".

Article 112 only stipulates a binding on the Finance Minister to lay only Financial Statement. It does not mean that if certain $taxe_s$ are levied on the long range basis, they cannot be levied. Take the example of Customs and Excise duties. Now, the long term fiscal policy primarily aims at income-tax and corporate taxes. But the bulk $_0$f the taxes that we receive is as a result of the Excise and Customs duty. The Finance Minister does not come every year with a statement on the first day that these grades which had t»en announced for the excise rates for the previous year will be applicable to this year also. This i_s a continuing pro;ess. and in the same manner as in the case of Customs duty and the Excise duty. If th_e long term fiscal policy has been formulated for purposes of income-tax and corporate tax, I dbn't think that there is any harm in it.

I have, however, to point out certain disturbing trends with regard to the

[Shri Ghulam Rasool Mattel Budget as such. Sir, the Seventh Plan envisages an outlay of Rs. 95,534 crores, out of which the Budgetary support would come to the tune of Rs. 44,846 Crores, and the resources of the public enterprises will be *R"*. 50,688 crores. If the resources for the Seventh Plan to the tunc of Rs. 50,688 crores are to come from the public sector, one has 10 understand, and I do not know whether in any speech made from that side or (his side any concrete suggestion has been offered as to how this projection made by the hon. Finance Minister with regard to the resources of the public sector of Rs. 50,688 crores should be maintained, if not increased. This is the thing. . .

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): May T inform the hon. Member that this quantum of PSU also includes internal and extra Budgetary support in which it includes these bonds also?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO The external borrowings...

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It includes borrowings also.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO:. . the internal borrowings are Rs. 26,697 crores. That is also there. But that is different. So, Sir, this is the situation. Now the situation with regard to the first year is disturbing. For the Revised Budget of 1985-86, the resources of the public enterprises have been put at Rs. 6,863 crores. The Budgetary support is kept at Rs. 13,231 crores. Now, for 1986-87. the resources of the public sector have been put at Rs. 8,683 crores whereas in the current year also, the actual portion is that the Budgetary support from the public sector fell short by about Rs. 2,000 crores in the first year. No projection has been made for the next year at a level which is Rs. 2,000 crores more. I think, this is not a, realistic picture and the hon.' Finance Minister shohuld look into the target that he has fixed. My point in making this out is that if the projections have been made, they should strictly be followed. He should see what the handicaps are in achieving the target of Rs. 8,683 crores. If those targets have to be achieved, I think, he has to have a close monitoring of the public sector enterprises. Sir, in the Consultative Committee of the Planning Commission of which the Prime Minister is the Chairman, we had along discussion about the public sector undertakings. I have said in that meeting what the present position is. What is the position? The present position is that a quarterly meeting is held, say, at the level of the Secretary of the concerned Ministry to know whether these targets have been achieved. What is really needed is that there should be constant monitoring all over, over all the public undertakings. If what you have stated, that is, to achieve your targets a constant monitoring has to be done, I have made certain suggestions in that Committee and you may kindly go through the proceedings of that Committee and see that monitoring *is* done in the manner in which I have stated.

Sir, the disturbing fact with regard to this thing is that during 1985-86, the public sector's own resources were projected at '53 per cent and the balance of 46 per cent was to come from the Budget Now, what is the actual position. This is disturbing me and this is when the Finance Minister should apply hit mind. Actually, the budgetary support wans hiah as 66 per cent, i.e., 19 per cent more than in the first year of the Plan. If this trend continues, it is very disturbing. So, I would request the hon. Minister that he should apply his mind to this point very seriously so that this point is taken note of.

Mr. Pranab Kumar Mukherjee made another point with regard to the projections of the next five years. Now, from the Budget at a glance. I find that the projecions have been amply stated for 1985-86, 1986.87. 1987-88, 1988-89, 1989-90.

There is nothing that has been hidden about it. What is needed is that how the resources should be mobilised to meet these expenses, that is the real prob-

lem. The hon. Finance Minister has not kept us in the dark about the next five years. He has clearly stated (hat even for each Ministry and even the sub-In. have been mentioned. But the point is that resource mobilisation has to be monitored. If for the first year our budgetary support to the resource plan fell short of 19 per cent, it will eat into our for the next five years. This is a point that needs to be taken care of by the hon. Finance Minister while he is thinking about resource mobilisation. (*I hell rings).* Sir. I take a few minutes more.

Sir. a lot is s>nid about income-tax. Income-tax forms only 8 per cent of the total income and out of this 8 per cent. 85 per cent goes back to the States statutorily. Against this, the indirect faxes from excise and custom about 80 per cent of the total tax revenue. Now, if emphasis has to be paid, if loopholes have to be plugged, it is this sector where loopholes have to be plugged in the customs and excise. Now, Sir, I have my own personal experience as a small manufacturer when the L. K. Jha Committee was constituted a few years back. I pointed out to them that when there is a multi-point excise duty, the result is obvious, that there is evasion on every point. The hon. Finance Minister stated that he will come out with; some long-term policy on indirect taxes. He should take into consideration that as far as possible this multi-point should be avoided because this breeds corruption and as a result of corruption^ you will not be able to get this thing. what is really needed.

Sir now 1 have to state with regard to the performance in 1985-86. Now, there are certain sectors in which, for instance, fadinaji had stated and I quote: "In a country where half the national income comes from farmimg agricultural self-reliance is the best of all..." This is what Indiraji said. And what is the performaiv in 1985? Performance in 1985 in agriculture was. the Budget figure is Rs. 918 crares and the revised figure comes to Rs. 859 crores; that means Rs. 59 crores less or a decrease of 7 per cent.

These are the key •sectors and he should see and ensure that in these key sectors, the budgetary provisions are really met. For instance, energy is another sector...

SHRI VISHWANATHPRATAP SINGH: In some areas, it is tied up with the States" resources,

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Of course, the strategy is that Stales have I also to take part in it but where it is from the Central pool, it should be adhered to. Now, Rs. 918 crores have been brought down to Rs. 859 crores. Similarly, in energy sector, for instance in power. The budget-outlay was Rs. 2395 pes and the crores. which means a shortfall of Rs. 208 crores. or 10 per cent less. So, I would request you that these issues should be taken care of.

Now I come to industry. For the village and small-scale industry, the budgeted figure is Rs. 313 crores; the revised ligurs is Rs. 298 crores. That means, there i« a shortfall of Rs. 15 crores'. This is the point that 1 want to make. As against this, in case of medium industry, the budgeted figure was Rs. 3670 crores and the revised figure is Rs. 4576 crores—an increase of Rs. 906 crores. And this in crease of Rs. 906 crores in medium and large-scale industries is there at the cost of small and village which should be avoided. Why I say this is that I think out of this Rs. 30.000 crores. the share of Jammu and Kashmir is only Rs. 7 crores. Now if this amoimt of Rs. 906 crores had been spent over and above the re, what is my share? I have been talking hoarse in this House and other bodies that Jammu and Kashmir should have its share. Whom should we contact? I have contacted the Prime Minis ten 1 have contacted the Industry Minister that something should be done in the next Seventh Plan where Kashmir should also come on the map because there Is such an imbalance that out of Rs. 30.000 crores. there is only Rs. 7 crores for i .Taninui and Kashmir.

[Shri Ghulam Rasool Matto]

with regard to tourism, 'the budgeted figure is Rs. 27 crores and the revised figure is Rs. 24 crores, that means," a shortfall of Rs. 3 crores. That means, Rs. 3 crores have not been spent. Sir, in the last three years, Kashmir has suffered a lot because we have had no tourists, first because of Punjab trouble and then other troubles. I would request the Minister to make allocations now as the tourist season is coming; Governor's rule is there; peace and amity has come back and he should make special allocation for tourism. That can be done only by having subsidy on rail fare, on air travel etc., so that more and more tourists come to Kashmir. My last point is about crop insurance. T am to the Finance Minister that he has included fruits cultivation. I would request him to include apples also and announce a policy in that regard so that those horticulturists, cultivators, may take advantage of it during the next season, because the flowering season starts in March-April.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam): Mr! Deputy Chairman, Sir, I rise to 'support the Budget presented by the hon. Finance Minister. Sir, I have had the privilege of being a Member since 1946, from the days of the Constituent Assembly, till today. I know what was the condition of our country in those days of British time. I know what was the state of affairs in the country at that time, before Independence. But then we were lucky enough that we had an outstanding personality in Pandit Jawaharlal Nehru, as Prime Minister who had the vision to develop the that it can, in a short span of time, compete with the most advanced countries in the world. It was during his leadership that many gigantic projects' like Bhakra Naneal, Bhilai, Rourkela etc. were estab'ished. This pace of industrial development has been continued after him and is being continued. After his death, after his sad demise, again, we were lucky that we had Shrimati Indira Gandhi as our Prime Minister who had the same vision to develop the country, in the way Pandit Nehru wanted and she did. Now, our young, energetic and dynamic Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, has taken over the responsibility of the country. Sir, it has become a habit with the Opposition to criticise the Government without any rhyme and reason. Now, Sir, what was the percentage of literacy earlier? Only 5 per cent. Now, it is 57 per cent or more. What as the per capita income earlier? Now, it is—as we have been told by the state Finance Minister the other day— Rs. 745 or so. What was the position in regard to education, in regard to the number of schools? There was not a single school then in the whole of a *pamhana* in my State. When I had to go to my house, I had to travel on. an elephant's back. Now, we have developed like anything. We now use motor cars for transport in remote villages. This has become a common thing even in the villages. When there has been such a tremendous economic development, I do not understand why the Omwition parties arc criticising us like anything.

lust now, the hon. Member from Jammu and Kashmir was talking about the promotion of tourism in his State. I had the privilage of visiting Kashmir so many time, when I was a member of the Constituent Assembly and otherwise. It was most backward like mv own State. Assam. Now, you know what is the extent to which Kashmir has developed. The Opposition parties have a right to criticise, but they should be constructive.

Sir, I do not know how much time I have, but I will try to touch only important points. Sir, I am glad that the Finance Minister has mentioned his Budget as anti poverty one as one of the main objectives to remove the poverty. Earlier, we had the *Garibi Hatan* programme. The present Budget has many important programmes in that direction and they .are reflecting the ideals and the vision of Pandit Jawaharlal Nehru and Shrimati Indira Gandhi,

Now I come to the specific problem with which I am very much concerned* the economic development of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other backward communities. The

economic gap between these communities and other advanced communities is widening. In this connection, I am happy that our young and energetic Prime Minister has taken up this problem and he is visiting many backward and tribal areas in our country to see by himself. He has already visited such areas in Madhya Pradesh, Orissa etc. The other day, he visited Arunachal Pradesh. Sir, I have been the founder Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the 9th December, 1968. I- know their plight. Same is the case in regard to bonded labour. I am very disappointed to be informed by the concerned Ministry that there are still seven lakh bonded labourers. In the Committee on the Welfare of Scheduled Caste3 and Scheduled Tribes, We had a proposal to remove the debt burden of these bonded labourers. What is their plight? When a person borrows Rs. 5, the compound interest on it is so high that with five years, it becomes Rs. 1,000. Therefore, unless the Government comes out with effective programmes and measures to help the bonded labourers, these people will not be able to come out of the debt trap.

In an independent country like outs we should not have the name of the bonded labour. Why? What is this bonded labour? Should we not be able to make them free from this bonded labour ours is developing country. If you compare our country with any other developing country, we have developed scientifically and technologically where we stand fifth. I therefore, request you to remove bonded labour altoeether from this country and bring them out from the clutches of *sahukars* and money-lenders. You should rehabilitate them somewhere by giving them some money and land all that.

Coming to other details, Prime Minister Indira Gandhi knew how to develop Scheduled Castes and the tribal people. She constituted the fourth financial committee, namely the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, where there is a provision for reservation in promotions also. As a member of this Committee when I examined this aspect, I am sony tG say that the bureaucrats are so much rigid that they are very much opposed to this reservation. I had to speak to them in very harsh words. I asked them, why they should argue, why they should not implement whatever has been accepted in the Parliament. The question is, the Parliament has accepted the provision of reservation in promotion also, but the bureaucrats are not going to implement it. I would like to request 'he Finance Minister to see to this aspect. I would also request him to see for 'himself the areas where the Scheduled Castes and Scheduled Tibes are residing in the cities and in other urban areas. He himself is a feudal and he knows it very well. 1 know from own experience that feudal friends are very friendly with us. They are more sensitive thatn the other people. I am saying so because I have friends like you. I had friends 1'ke Dr. Karan Singh, Dr. Karan Singh and others. They know how our tribal people have been kept in dark during the feudal age.

Coming to the other details, the literacy is only 14 per cent in case of Scheduled Caste but it is only 8 per cent in dase of Scheduled Tribes. In the field of employment, they are in a dilapidated condition. The employment percentage m regard to Scheduled Castes is 2.39 whereas it is 0.59 in regard to Tribal people. Can you imagine- the nlight of the tribal people? in-spite of the drive given by our Prime Minister, in spite of the drive given by our lamented Prime Minister, Shrimati Indira gandhi we are still in this condition. So, I would request you to '00k into 1 this nersonally, see that they arc not in a dilapidated condition. After coming to this House I have been appointed again member on the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I I have had the privilege so looking into I the condition of the tribal people, since the time I became Member of Parliament, in Rajya Sabha. For a few years I was not a Member of this House because of the agitations in Assam Stale. Oftefwise, I have always tried to look to their conditions, but I am very sorry to say that the i Plight of the tribal people has not improv-\ ed at all, it is the same what it was In

[Shri Dharanidhar Basumatari]

the beginning. I had to use very strong words against the bureaucrats by saying that unless and until the recommendations of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are implemented their condition cannot be improved. *{Time bell rings)* Since you have rung the bell, I will only request the Finance Minister and the Prime Minister, as they are one unit, ^ think of the development of the country for the times to come, for the future generation.

STATEMENT BY MINISTER—

RE Report of the Court of investigation into 'Kanishka' Air crash

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI .JAGDISH TYTLER). Mr. Deputy Chairman, Sir, on the morning of 23rd June* 1985, Air India Boeing 747 aircraft VT-EFO 'Kanishka' was On a scheduled passer flight (AI-182) from Montreal and was proceeding *to* London on route to Delhi and Bombay. The aircraft was being monitored On the radarscope of Shannon airport in Ireland. At 0714 GMT it sudden, ly disappeared from the radarscope and the aircaft which Was flying at an altitude of approximately 31,000 feet plunged into the Atlantic Ocean off the South West Coast of Ireland 'at position latitude 51 3.6' N and longitude 12° 49' W. This was the worst air disaster in the history of Indian aviation wherein all the 307 passengers and 22 crew members perished.

The Government of India, had appointed Justice B. N. Kirpal. Judge of the Delhi High Court, to carry out la formal investigation in to this accident. The Court was assisted by five assessors. It carried out detailed examination of the Digital Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder. The entire wreckage lying at the bottom of the sea was mapped and photographed. Part of the wreckage was recovered and examined in details at the facilities of Bhabha Atomic Research Centre, Bombay. In all, 13 witnesses were examined by the Court which included representatives of aircraft manufacturers, Royal Canadian Mounted Police, Canadian Aviation Safety Board, Director General of Civil Aviation India Air India, Bhabha Atomic Research Centre, Doctors of Royal Air Force, United Kingdom, and the Indian.' Air Force. Post mortem reports from the doctors from Ireland, report of Structures Group consituted I by the Court, Cockpit Voice Recorder Analysis Reports of experts of Bhabha Atomic Research Centre, Canadian Aviation Safety Board, National Transportation Safety Board, U.S.A, and Accidenf Investigation Branch 0f United Kingdom and the report of the Inspector of Accidents, Civil Aviation Department, India were examined by the Court, The Court 1 visited Ireland and Narita Airport, Tokyo.

The Court has submitted its report on ' the 26th February, 1986 to the Government. All thg five assessors have signed Che report in token of their 'agreement with the conclusions and recommendations. There is, no minute of dissent.

On the basis of the circumstantial and I direct evidence, the Court has concluded 1 that the accident was caused by an explosion °f a bomb in the forward cargo hold of the aircraft. The Court has also made some recommendations. They relate *to* International Civil Aviation Organi-. sation, International Air Transport Association. Airlines, Government -and ; manufacturers of aircraft, on matters like air safety, air security, etc. These recommendations are being examined by Government for further action.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir. this is one of the worst type of accident ever to happen to any of our aircraft. All the passengers plunged to death. But it is not clear from the statement—and this is what I would like to know—how many passengers died and if all the bodies were found or some are still missing.

Secondly, it shows that our security arrangement of what we call the marshals and other security staff was not up to the mark—whether it is for internal flights or for international flights. Therefore, what recommendations have been made by this Court of Inquiry to streny-then the security so that such incidents canont and will not happen in the future.